



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]
No. 414]

नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 7, 1986/बाद्रा 16, 1908
NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 7, 1986/BHADRA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1986

उद्घोषणा

सा.का.नि. 1061 (प्र).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्न-
लिखित उद्घोषणा संविधानण के सुनावने प्रक्रिया की जा रही है।

यह, मुझे, भारत के राष्ट्रपति, द्वेष मिह को जम्मू व कश्मीर राज्य
के राज्यपाल में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इस रिपोर्ट तथा मुझे
भारत अन्य गृहनाल पर विचार करने के बाद मैंने समझान हो गया
है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का आसन
भारत के संविधान, जैसा कि वह उस राज्य पर लागू है (जिसे इसमें
इसके पश्चात 'संविधान' कहा गया है) और जम्मू व कश्मीर के संविधान
(जिसे इसके पश्चात 'राज्य संविधान' कहा गया है) के उपबंधों
के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

अतः, प्रबंध में, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
तथा उन नियान्त मुझे समर्पण करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग
करते हुए एतद्वारा उद्धारणा करना है ति मैं—

(क) संविधान और राज्य संविधान के अधीन उक्त शक्ति की सरकार
के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित अधिकार
उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों भारत के राष्ट्रपति के
रूप में स्वयं संभालता हैं;

(ख) उद्घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विभाग मंडल की
शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग उसके प्राधिकार के प्रयोक्तव्य
होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुबंधिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ
जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए
मुझे आवश्यक या पार्याप्त प्रतीत होते हैं, यथातः—

(i) पूर्वोत्तर के अनुसार, इस उद्घोषणा के खण्ड (क) के
प्राधार पर मेरे द्वारा पंजाब गण गृह्यों तथा शक्तियों
का प्रयोग करने में मेरे निए, भारत के राष्ट्रपति के
अपि में उस सीधा तरफ जिन तक मैं टीक चम्हू,
उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करता
विधिपूण होगा;

(ii) मनिधन के तथा राज्य संविधान के निम्नलिखित
उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलम्बित किया
जाता है, यथात्,—

संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रथम परन्तुक का उत्तरी
भाग जिनमें का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य विवाह-
महल के प्रति निर्देश से है, और उस अनुच्छेद का
दूसरा परन्तुक;

संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जिसने का संबंध भारत के विवरक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष किए प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

राज्य संविधान की घाराएं 35 से 41 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) घारा 45 का उतना भाग जिसने का संबंध राज्य सरकार के विधियों के बीच पार्श्व के बंटवारे से है, घारा 44, घारा 53 की उप-घारा (1) और उपघारा (2) का खंड (क), घारा 34, 55, 56 तथा 57 घारा 58 के खंड (ख) और (ग) और उसका पहला परन्तु, घारा 39, घारा 60, घारा 61 भी उपघारा (2), जहाँ तक उसका संबंध घारा 58 के खंड (ग) और पहले परन्तु में तथा घारा 60 से है;

घाराएं 65, 66, 67, 71 और 72, घाराएं 74, 25 और 76, घारा 77 की उपघारा (3) तथा (4), घाराएं 85 से 88 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) और घारा 137 का उतना भाग जिसने का संबंध जापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

(iii) संविधान में, और राज्य के संविधान में, राज्यपाल के प्रति किसी निवेश का अर्थ उक्त राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निवेश लगाया जाएगा, और संविधान में तथा राज्य के संविधान में राज्य के विधानमंडल या उसके सदनों के प्रति, यथास्थिति, किसी निवेश का, जहाँ तक उसका संबन्ध उसके छहों और शक्तियों से है, अर्थ, अब तक सर्वभौम अध्यय्या अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निवेश लगाया जाएगा, और विशिष्ट तथा राज्य के संविधान की घारा 91 में राज्यपाल के प्रति और राज्य के विधानमंडल अध्यय्या उसके सदनों के प्रति निवेश का अर्थ क्रमः राष्ट्रपति के प्रति और संसद या उसके सदनों के प्रति निवेश लगाया जाएगा :

परन्तु इसमें की कोई बात राज्य संविधान की घारा 26 की उपघारा (1), घाराएं 27 से 31 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), घारा 122, घारा 143 और दूसरी अनुसूची के पैरा 1 से 8 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं ढाले गी और न राष्ट्रपति को इस खंड के उपखंड (i) के अधीन, उस सीमा तक जहाँ तक यह ठीक रामबंद, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम के कार्य करने से निवारित करेगी ;

(iv) संविधान में, या राज्य संविधान में राज्य के विधानमंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निवेश का ऐसे कर्त्ता लगाया जाएगा जाने वह अधिनियमों या विधियों को भी भासाविष्ट करता है जो इस उद्देश्यपूर्ण के आधार पर भवित्व घारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट धन्य प्राविकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करने हुए बनाए गए हैं, और जम्मू व कश्मीर साधारण खंड अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम मंड्या 20) और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जिसका राज्य की विधियों पर लागू होता है, ऐसे किसी अधिनियम

या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा जाने यह उत्तराधिनियम हो।

मई 1986,
दिनांक 7 सितम्बर, 1986

जैल सिंह,
राष्ट्रपति

[का. सं. 11011/4/86-क]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th September, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1061(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :

Whereas, I, Zail Singh, President of India, have received a report from the Governor of the State of Jammu and Kashmir and after considering the report and other information received by me. I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India, as applicable to that State (hereinafter referred to as "the Constitution") and of the Constitution of Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as "the State Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I —

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the State Constitution;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—
 - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
 - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution and of the State Constitution is hereby suspended, namely :—
 - so much of the first proviso to article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the Legislature of the State and the second proviso to that article;
 - so much of clause (2) of article 151 of the Constitution as relates to the laying before the Legislature of the State of

the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

sections 35 to 41 (both inclusive), so much of section 43 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State, section 44, sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 53, sections 54, 55, 56 and 57, clauses (b) and (c) of section 58 and the first proviso thereto, section 59, section 60, sub-section (2) of section 61 so far as it relates to clause (c) of, and the first proviso to, section 58 and to section 60, sections 65, 66, 67, 71 and 72; sections 74, 75 and 76 sub-sections (3) and (4) of section 77, sections 85 to 88 (both Inclusive) and so much of section 137 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State of the State Constitution;

(iii) any reference in the Constitution and the State Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference in the Constitution and the State Constitution to the Legislature of the State or the House thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in section 91 of the State Constitution to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively :

Provided that nothing herein shall affect the provisions of sub-section (1) of section 26, sections 27 to 31 (both inclusive), section 122, section 143 and paragraph 1 to 8 (both inclusive) of the Second Schedule to the State Constitution or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution or in the State Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Jammu and Kashmir General Clauses Act, 1977 (Act No. XX of 1977) and so much of the General Clauses Act, 1897 10 of 1897 as applies to State lays, shall

have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi.

The 7th September, 1986.

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[F. No. 11011/4/86-K]

ग्राहिता

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1986

सा. का. नि. 1062(ग).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वेसांवित्ता के अनुकूल प्रतिशित किया जा रहा है:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज सितम्बर, 1986 के सातवें दिन जारी की गई उद्योगपाणी के खंड (ग) के उप-खंड (i) के अनुसरण में, मैं एशियारा निदेश देता हूँ कि जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के सभी इत्य संविधान और जम्मू व कश्मीर के संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रत्येक नियमित कानून उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तात्व सभी एकान्तां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्योगपाणी के खंड (क) के प्राविधिक पर स्वयं समान लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण के प्रध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तात्व होंगी।

नई दिल्ली,
विनांक 7 सितम्बर, 1986

पैमाने
राष्ट्रपति

[का. स. 11011/4/86-क]
सी. जी. सोमेया, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th September, 1986

G.S.R. 1062(E).—The following Order by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the Seventh day of September, 1986, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Jammu and Kashmir and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the Constitution of Jammu and Kashmir or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi:
The 7th September, 1986

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[F. No. 11011/4/86-K]
C. G. SOMIAH, Home Secy.

